

TODAY'S ANALYSIS

(आज का विश्लेषण) (10 January 2025)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- प्रधानमंत्री द्वारा 18वें 'प्रवासी भारतीय दिवस' सम्मेलन का उद्घाटन किया गया
- भारत द्वारा अफ़ग़ानिस्तान से उच्च स्तर पर बातचीत करने का निर्णय क्यों
 लिया गया है?
- 'जीनोम इंडिया' परियोजना के तहत 10,000 मानव जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया गया
- MCQ

प्रधानमंत्री द्वारा 18वं 'प्रवासी भारतीय दिवस' सम्मेलन का उद्घाटन किया गया:

परिचय:

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी को भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण का उद्घाटन किया, जिसमें उनका भाषण 'विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों



के योगदान' की थीम पर केंद्रित था। उन्होंने इस तिथि के महत्व पर भी ध्यान दिलाते हुए कहा कि "वर्ष 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी लंबे समय तक विदेश में रहने के बाद भारत वापस आए थे"।

- उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम हर दो साल में एक बार "अपनी मातृभूमि के लिए प्रवासी भारतीयों के योगदान का सम्मान करने" के लिए आयोजित किया जाता है।
- विदेश मंत्रालय के अन्सार, 3.5 करोड़ से अधिक प्रवासी भारतीय विदेश में रहते हैं।

प्रवासी भारतीय दिवस का इतिहास और उत्पत्ति:

 भारत और विदेशों में रहने वाले भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों का जश्न मनाने के लिए, इन भारतीयों को समर्पित एक दिन मनाने का विचार इस सहस्राब्दी की शुरुआत में आया था।

- इस पहल की घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 9 जनवरी, 2003
 को भारत सरकार द्वारा गठित भारतीय प्रवासियों पर उच्च स्तरीय एल.एम.
 सिंघवी समिति की सिफारिश पर की थी। यह वही दिन था जब महात्मा गांधी
 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे; बाकी सब इतिहास है।
- यह दिवस सिर्फ़ एक उत्सव से कहीं बढ़कर बन गया है क्योंकि यह भारतीय प्रवासियों को अपनी चिंताओं को संबोधित करने और एक नया दृष्टिकोण सामने लाने का मंच प्रदान करता है।
- 2015 से, महात्मा गांधी की वापसी के शताब्दी वर्ष के बाद से, बैठक के प्रारूप को संशोधित किया गया ताकि इसे हर दो साल में एक बार आयोजित किया जा सके।

भारतीय डायस्पोरा या प्रवासियों का इतिहास:

डायस्पोरा शब्द की जड़ें ग्रीक शब्द डायस्पेरो से जुड़ी हैं, जिसका अर्थ है फैलाव।
 गिरमिटिया व्यवस्था के तहत गिरमिटिया मजदूरों के रूप में पूर्वी प्रशांत और
 कैरेबियाई द्वीपों में पहली बार भारतीयों के समूह को ले जाने के बाद से भारतीय
 प्रवासियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है।

- 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में हजारों भारतीयों को ब्रिटिश उपनिवेशों में बागानों में काम करने के लिए उन देशों में भेजा गया था, जो 1833-34 में 'दास प्रथा' उन्मूलन के कारण श्रम संकट से जूझ रहे थे।
- भारतीयों के प्रवास की दूसरी लहर के हिस्से के रूप में, लगभग 20 लाख भारतीयों
 को खेतों में काम करने के लिए सिंगापुर और मलेशिया ले जाया गया।
- तीसरी और चौथी लहर में भारतीय पेशेवरों ने पश्चिमी देशों की ओर रुख किया
 और तेल उछाल के मद्देनजर खाड़ी और पश्चिम एशियाई देशों में काम करने वाले
 भारतीय श्रमिकों ने इन देशों में रुख किया।
- संयुक्त राष्ट्र के विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय प्रवासियों की संख्या में
 दुनिया की सबसे अधिक है, उसके बाद मैक्सिको, रूस और चीन का स्थान है।

प्रवासी भारतीयों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है?

- प्रवासी भारतीयों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) और भारत के प्रवासी नागरिक (OCI)।
- अनिवासी भारतीय (NRI) वे भारतीय नागरिक हैं जो विदेशी देशों के निवासी हैं लेकिन उनके पास भारत की नागरिकता या पासपोर्ट है।

- PIO श्रेणी को 2015 में समाप्त कर दिया गया और OCI श्रेणी में विलय कर दिया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार, PIO एक विदेशी नागरिक (पाकिस्तान, अफगानिस्तान बांग्लादेश, चीन, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को छोड़कर) को संदर्भित करता है, जिसके पास किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट था, या जो या उसके माता-पिता/दादा-दादी/परदादा-परदादी में से कोई एक भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित अनुसार भारत में पैदा हुआ और स्थायी रूप से निवास करता था, या जो भारत के नागरिक या PIO का जीवनसाथी है।
- वर्ष 2006 में OCI की एक अलग श्रेणी बनाई गई थी। OCI कार्ड उस विदेशी नागरिक को दिया जाता था जो 26 जनवरी, 1950 को भारत का नागरिक होने के योग्य था, 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था, या किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित था जो 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना। ऐसे व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे, जो पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक नहीं थे, को छोड़कर, भी OCI कार्ड के लिए पात्र थे।

भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का महत्व:

विदेश मंत्रालय के 2024 के अंत के आंकड़ों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में
 54 लाख प्रवासी भारतीय हैं, संयुक्त अरब अमीरात में यह संख्या 35 लाख,



कनाडा में 28 लाख और सऊदी अरब में 24 लाख है। यह विशाल आबादी अपने देश में बड़ी रकम भेजती है। 2023 में यह राशि लगभग 125 अरब डॉलर थी।

- लेकिन इन धनराशि से परे भी, प्रवासी समुदाय देशों के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में, प्रवासी भारतीयों के सदस्य राजनीति में तेजी से दिखाई दे रहे हैं।
- भारत में राजनीतिक दलों ने पिछले कुछ वर्षों में प्रवासी भारतीयों तक अपनी पहुंच
 बढ़ाने का प्रयास किया है।

भारत द्वारा अफ़ग़ानिस्तान से उच्च स्तर पर बातचीत करने का निर्णय क्यों लिया गया है?

चर्चा में क्यों है?

तालिबान शासन के साथ पहली उच्च
स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता में विदेश सचिव
विक्रम मिसरी ने 8 जनवरी को दुबई में
अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश
मंत्री आमिर खान म्ताकी से म्लाकात की।



- अब तक संयुक्त सचिव स्तर के एक भारतीय अधिकारी मुत्ताकी और रक्षा मंत्री
 मोहम्मद याकूब सिहत तालिबान के मंत्रियों से मिलते रहे हैं। लेकिन विदेश सचिव
 मिसरी की यह मुलाकात एक नया कदम है, जो भारत सरकार की ओर से उच्च
 स्तरीय आधिकारिक वार्ता का संकेत देता है।
- विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

भारत द्वारा तालिबान से वार्ता स्तर को अपग्रेड करने का क्या कारण है?

- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन यह भारत द्वारा अपने राष्ट्रीय और सुरक्षा हितों को सुरक्षित करने का एक प्रयास है, जिसमें कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं।
- भारत, जो खेल की स्थिति पर नजर रख रहा है, जल्दी ही इस निष्कर्ष पर पहुंच
 गया कि आधिकारिक मान्यता दिए बिना आधिकारिक जुड़ाव के स्तर को उन्नत
 करने का यह सही समय है, नहीं तो अफगानिस्तान में वर्षों के निवेश को खोना
 पड़ सकता है।
- भारत द्वारा उच्च स्तर पर बातचीत करने के कदम के पीछे पांच प्रमुख कारक:
 - > तालिबान का हितैषी और सहयोगी पाकिस्तान एक विरोधी बन गया है;
 - > ईरान काफी कमजोर हो गया है;
 - रूस अपना युद्ध लड़ रहा है; और
 - अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की तैयारी कर रही है।
 - >> चीन तालिबान के साथ राजदूतों का आदान-प्रदान करके अफगानिस्तान में अपनी पैठ बना रहा है।
 ADDRESS:

भारत शुरू से ही तालिबान के साथ जुड़ाव को बनाये रखे हुए था:

- उल्लेखनीय है कि अगस्त 2021 के मध्य में अशरफ गनी सरकार को हटाने और काबुल पर कब्जा करने के बाद से ही तालिबान भारत के साथ अधिक सिक्रय जुड़ाव का आह्वान कर रहा था। भारत ने अपना पहला कदम 31 अगस्त, 2021 को ही उठाया था, जब कतर में उसके राजदूत दीपक मित्तल ने शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनिकजई (एक भारतीय सैन्य अकादमी के कैडेट जो बाद में तालिबान के उप विदेश मंत्री बने) के नेतृत्व में तालिबान के दोहा कार्यालय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।
- इसके बाद, भारतीय अधिकारियों ने इस जुड़ाव को जारी रखा, जिसकी शुरुआत विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (पािकस्तान, अफगािनस्तान और ईरान) जे पी सिंह ने जून 2022 में तािलबान के प्रमुख नेताओं से की। इससे कुछ दिनों बाद काबुल में भारतीय दूतावास में एक तकनीकी टीम भेजने का रास्ता साफ हो गया।
- सिंह और अन्य अधिकारियों ने कम से कम चार बैठकें की, जिसकी घोषणा बाद में दुबई में विदेश सचिव की बैठक आयोजित होने से पहले की गई थी। इस बैठक में जो सीमित जुड़ाव के रूप में शुरू हुआ था और जिसे गुप्त रखा गया था, वह पिछले एक साल में परिस्थितियों के बदलने पर आसान हो गया।

तालिबान और पाकिस्तान एक दूसरे के विरोधी बन गए हैं:

- पाकिस्तान, जिसने 2021 में काबुल के सेरेना होटल में तत्कालीन ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के साथ चाय की चुस्की लेते हुए तालिबान के उदय का जश्न मनाया था, अब तालिबान के साथ तनावपूर्ण संबंधों में है। उस समय भारत इस बात से चिंतित था कि तालिबान पाकिस्तान की ISI को कैसे जगह देगा और भारत और भारतीय हितों के खिलाफ अफगान धरती का इस्तेमाल कैसे करेगा।
- लेकिन वर्तमान में तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव इस स्तर पर आ गया
 है कि अफ़ग़ानिस्तान ने दावा किया है कि 24 दिसंबर को अफगानिस्तान के
 पिक्तका प्रांत में पिकिस्तानी हवाई हमलों में मिहलाओं और बच्चों सिहत कम से
 कम 51 लोगों की मौत हो गई।
- 6 जनवरी को, भारत ने इस पािकस्तानी हवाई हमलों की भर्त्सना करते हुए पर अपना पहला बयान दिया। भारत ने निर्दोष नागरिकों पर किसी भी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की है।

इस क्षेत्र में ईरान का काफी कमजोर होना:

• 2024 के उत्तरार्ध में, ईरान को अपमानजनक झटका लगा, क्योंकि इजरायल हिज्बुल्लाह और हमास को खत्म करने में कामयाब रहा। इतना ही नहीं, इजरायल

ने ईरान पर सीधे मिसाइल हमले भी किए, जो 1979 की ईरानी क्रांति के बाद पहला हमला था।

रूस द्वारा तालिबान के साथ संबंध बहाली के प्रयास:

- पिछले तीन वर्षों में, रूस यूक्रेन में अपने युद्ध में उलझा हुआ है, और तालिबान के साथ पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जुलाई
 2024 में कहा कि तालिबान अब आतंकवाद से लड़ने में एक सहयोगी है।
- रूस को अफगानिस्तान से लेकर मध्य पूर्व तक के देशों में स्थित इस्लामी समूहों
 से एक बड़ा सुरक्षा खतरा दिखाई देता है। और दिसंबर में जब सीरियाई राष्ट्रपति
 बशर अल-असद का शासन गिर गया, तो इसने एक प्रमुख सहयोगी खो दिया।
- दिसंबर 2024 में, रूसी संसद ने एक कानून के पक्ष में मतदान किया, जो तालिबान को मास्को की प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाना संभव बना देगा।

अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की वापसी:

भारत की इस रणनीतिक अनिवार्यता को तेज करने में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप
 की वापसी भी जिम्मेदार है। क्योंकि उसके बाद तालिबान के साथ नए अमेरिकी
 प्रशासन की ओर से बातचीत हो सकती है।

• आखिरकार, यह ट्रंप प्रशासन ही था जिसने तालिबान के साथ बातचीत शुरू की थी और अमेरिकी सैन्य वापसी पर एक समझौते पर पहुंचा था।

चीन की अफगानिस्तान में खाली जगह भरने की कोशिश:

- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन भी अफगानिस्तान में रास्ता बनाने और प्राकृतिक संसाधनों पर नज़र रखने के खेल में शामिल हो गया है। सितंबर 2023 में, चीन ने काबुल में अपना राजदूत भेजा और 2024 की शुरुआत में, चीन ने अपने राजदूत के रूप में तालिबान के प्रतिनिधि को स्वीकार किया। चीन ने अफगान केंद्रीय बैंक की विदेशी संपत्तियों पर लगी रोक हटाने का आह्वान किया है।
- भारत का मानना है कि चीन अपनी बेल्ट एंड रोड पहल के तहत अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों के विकास पर नज़र रखे हुए है। भारत ने देखा कि चीन अमेरिका, यूरोप, पश्चिम और भारत द्वारा छोड़े गए खालीपन को भर रहा है।

भारत के लिए अफगानिस्तान में आगे का रास्ता:

इसिलए, दुबई में बैठक का समय इन कई गितशील मुद्दों द्वारा निर्धारित किया
 गया है, जिन्होंने खेल की स्थिति को पिरभाषित किया है - अनिवार्य रूप से भारत
 को तालिबान के साथ जुड़ाव के केंद्र में रखा है।

- अफगानिस्तान में भारत की मुख्य चिंता यह रही है कि अफगानिस्तान में आतंकवाद पनपना नहीं चाहिए और सभी अनुमानों के अनुसार, सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है हालांकि महिलाओं के अधिकारों को कुचल दिया गया है, जिससे भारत को बहुत परेशानी हुई है।
- तालिबान ने अब तक भारतीय हितों और दूतावास परिसर सहित सुविधाओं के लिए सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित की है। और उन्होंने कहा है कि वे इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत से लड़ रहे हैं, जिससे भारत भी सावधान है। भारतीय अधिकारियों के साथ पहली बैठक से ही, तालिबान ने इस बात को रेखांकित किया है कि "मानवीय सहायता और विकास परियोजनाओं की बात करें तो भारत की मदद का स्वागत है"।
- 2021 की बैठक में, तालिबान अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत की परियोजनाएं जिनका पिछले 20 वर्षों में अनुमानित मूल्य 3 बिलियन अमरीकी डॉलर है "बेहद उत्पादक" रही हैं और वे चाहेंगे कि "भारत अफगानिस्तान में निवेश करता रहे"।

'जीनोम इंडिया' परियोजना के तहत 10,000 मानव जीनोम

डेटाबेस लॉन्च किया गया:

चर्चा में क्यों है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी को 'जीनोम इंडिया' परियोजना के पूरा होने की घोषणा की, इसे देश में "जैव प्रौद्योगिकी क्रांति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर" बताया और 10,000 भारतीयों



के अनुक्रम डेटाबेस का अनावरण किया। इन 10,000 व्यक्तियों के अनुक्रमण से एकत्र किए गए डेटा को अब भारतीय जैविक डेटा केंद्र (IBDC) में प्रबंधित पहुँच के माध्यम से शोधकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा।

 प्रधानमंत्री मोदी ने इस परियोजना को भारत की जैव प्रौद्योगिकी क्रांति में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जिसमें एक विविध आनुवंशिक संसाधन के निर्माण पर जोर दिया गया।

'जीनोमइंडिया (GenomeIndia)' परियोजना क्या है?

- जनवरी 2020 में लॉन्च की गई जीनोम इंडिया परियोजना का उद्देश्य भारत की आबादी के भीतर आनुवंशिक विविधताओं की एक व्यापक सूची बनाना था, जो देश की विशाल आनुवंशिक विविधता को दर्शाती है। विभिन्न जनसंख्या समूहों के 10,000 व्यक्तियों के संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण का संचालन करके, इस पहल का उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अद्वितीय आनुवंशिक विविधताओं का एक संदर्भ सेट तैयार करना है।
- हमारे विकास के इतिहास को समझने, विभिन्न रोगों के लिए आनुवंशिक आधार की खोज करने और भविष्य के उपचार बनाने के लिए आनुवंशिक विविधता का मानचित्र आवश्यक है।
- यह परियोजना 20 से अधिक अग्रणी संस्थानों के संघ द्वारा शुरू की गई थी,
 जिसमें नई दिल्ली, मद्रास और जोधपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT);
 बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (IIS); वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान
 परिषद (CSIR); और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र (BRIC) शामिल
 हैं।

जीनोम अन्क्रमण एवं मानव जीनोम क्या होता है?

- उल्लेखनीय है कि जीनोम अनुक्रमण, एक प्रयोगशाला तकनीक है जिसका उपयोग किसी जीव या कोशिका की संपूर्ण आनुवंशिक संरचना या मानव जीनोम को डिकोड करने के लिए किया जाता है, जो परियोजना के केंद्र में है।
- मानव जीनोम मूलतः एक जैविक निर्देश पुस्तिका है जो हमें अपने माता-पिता से विरासत में मिलती है। यह केवल चार अक्षरों, A, C, G, और T के साथ लिखा गया एक ग्रंथ है चार आधार जो हर किसी की अनूठी आनुवंशिक संरचना बनाने के लिए एक साथ आते हैं।
- संपूर्ण मानव जीनोम में लगभग 3 अरब जोड़े क्षार होते हैं। इसमें व्यक्ति के भौतिक स्वरूप को बनाने और जीवन भर इसे बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी जानकारी शामिल है।

देश में जीनोम अनुक्रमण के अध्ययन के क्या लाभ हैं?

• यह विभिन्न बीमारियों के लिए आनुवंशिक आधार या आनुवंशिक जोखिम कारकों की पहचान करने में मदद कर सकता है। जैसे एक उत्परिवर्तन, MYBPC3, जो कम उम्र में कार्डियक अरेस्ट का कारण बनता है। यह भारतीय आबादी के 4.5% में पाया जाता है लेकिन विश्व स्तर पर दुर्लभ है। इसी तरह LAMB3 नामक एक

अन्य उत्परिवर्तन त्वचा की घातक स्थिति का कारण बनता है। यह मदुरै के पास लगभग 4% आबादी में पाया जाता है, लेकिन इसे वैश्विक डेटाबेस में नहीं देखा जाता है।

- भारतीय जीनोम डेटाबेस का आनुवंशिक रोगों के उपचार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
 उल्लेखनीय है कि यह लिक्षित उपचारों में मदद कर सकता है, विशेष रूप से दुर्लभ बीमारियों के लिए जो आमतौर पर आनुवंशिक विसंगतियों से उत्पन्न होती हैं।
- यह प्रतिरोध-संकेत देने वाले वेरिएंट की पहचान करने में भी मदद कर सकता है उदाहरण के लिए, जीन जो कुछ आबादी में कुछ दवाओं या एनेस्थेटिक्स को अप्रभावी बना सकते हैं। एक उदाहरण दक्षिण भारत के वैश्य समुदाय का एक समूह है, जिनके पास सामान्य एनेस्थेटिक्स को ठीक से संसाधित करने के लिए जीन की कमी है। इस समूह के लिए, ऐसे एनेस्थेटिक्स के उपयोग से मृत्यु हो सकती है।

जीनोम अनुक्रमण से जुड़ी कुछ चुनौतियां:

निःसंदेह, बड़े पैमाने पर जीनोम अनुक्रमण नए दरवाजे खोलते हैं, वे नई चुनौतियों
 का भी सामना करते हैं, विशेष रूप से इन जीनोम की नैतिकता और उन तक
 पहंच और उन पर आधारित खोजों के संबंध में।



• अमेरिका जैसे देशों ने भी आनुवंशिक डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए सिक्रय रूप से नियामक ढांचे बनाए हैं, जैसे कि आनुवंशिक सूचना गैर-भेदभाव अधिनियम की शर्तों का उपयोग करके बीमा और रोजगार भेदभाव को रोकना।



MCQs

- चर्चा में रहे 'प्रवासी भारतीय दिवस' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 - 1. इस पहल की शुरुआत 9 जनवरी, 2003 को भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रवासियों पर उच्च स्तरीय एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर की थी।
 - 2. यह वही दिन था जब महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(c)

- प्रवासी भारतीयों की वर्गीकृत तीन श्रेणियों में से एक, भारत के प्रवासी नागरिक (OCI) की श्रेणी कब श्रू की गयी थी?
 - (a) वर्ष 2002 में
 - (b) वर्ष 2006 में
 - (c) वर्ष 2009 में
 - (d) वर्ष 2015 में

Ans:(b)

- चर्चा में रहे 'जीनोमइंडिया' पिरयोजना के संदर्भ में निम्निलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 - 1. इस परियोजना का उद्देश्य भारत की आबादी के भीतर आनुवंशिक विविधताओं की एक व्यापक सूची बनाना था, जो देश की विशाल आनुवंशिक विविधता को दर्शाती है।
 - 2. इसके तहत एकत्रित 10,000 मानव जीनोम डेटाबेस को ओपन सोर्स के रूप में आम लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
 - (a) केवल 1
 - (b) केवल 2
 - (c) 1 और 2 दोनों
 - (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(a)

- 4. हाल ही में भारत द्वारा अफ़ग़ानिस्तान के तालिबान से उच्च स्तर पर बातचीत करने का निर्णय, निम्नलिखित में से किस/किन कारण/कारणों से लिया है?
 - (a) तालिबान और पाकिस्तान का एक दूसरे के विरोधी बनना।
 - (b) रूस और तालिबान के साथ संबंध का बेहतर होना।
 - (c) इस क्षेत्र में ईरान का काफी कमजोर होना।
 - (d) उपर्युक्त सभी कारणों से है।

Ans:(d)

- 5. चर्चा में रहे 'जीनोमइंडिया' परियोजना के उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 - 1. यह विभिन्न बीमारियों के लिए आनुवंशिक आधार या आनुवंशिक जोखिम कारकों की पहचान करने में मदद कर सकता है।
 - 2. यह लक्षित उपचारों में मदद कर सकता है, विशेष रूप से दुर्लभ बीमारियों के लिए।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) उपर्य्क्त में से कोई नहीं

Ans:(c)